



सुविचार
 'भगवान
आपको
आशीर्वाद देने
के साथ
साथ चुनौतियां
देकर परवता
भी हैं'

-अज्ञात

लो

कसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जा रहे पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही अब इन राज्यों में चुनावी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश यांग होगा जहां दो चरण में मतदान कराया जा रहा है, जबकि सभी अन्य चार राज्यों में एक ही चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। सात नवंबर को पहला मतदान होगा। उस दिन मिजोरम और छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। सत्रह नवंबर को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए और मध्यप्रदेश में इसी दिन सभी सीटों के लिये मतदान होगा। उसके एक-एक हफ्ते के अंतर पर राजस्थान और तेलंगाना में मतदान की बारी आयेगी। नवीती तीन दिन बिसंबर को आयेगी। इस तरह कुल छह्यांस दिनों में चुनाव संपन्न होंगे। राजनीतिक दल इनके लिए पहले से तैयारी में जुट गए थे। तमाम बड़े नेताओं, मंत्रियों आदि की रैलियां महीना भर पहले से होने लगी थीं। यहां है, मतदान की तारीखें घोषित होने की ही इंतजार था। वैसे राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में

भाजपा और कांग्रेस के बीच काटे की टकराव अब तक तो साफ नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल एक-जुट हैं। इस तरह इन चुनावों में सरगमी कुछ अधिक रहने की संभावना है। हर राजनीतिक दल के बड़े नेता चुनाव प्रचार में उत्तरोंगे। इसलिए भी सुक्ष्म कारणों से निर्वाचन आयोग ने मतदान को इतनी लंबी अवधि में केलाने का फैसला किया होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल भाषण इलाकों में हमेशा अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत रही है। कोशिश की जाती है कि उन इलाकों में लोग अधिक संचाला में घरों से निकलें और उन्हें मताधिकार का उपयोग करें। इसलिए भी वहां दो चरण में मतदान का फैसला किया गया। हालांकि जब से मरीजों से मतदान कराए जाने लगे हैं, तब से अपेक्षा की जाती है कि मतदान और नीतों के बीच की अवधि कम से

कम रहे। कम से कम चरणों में मतदान कराए जाएं। मगर मरीजों के उपयोग के बाद भी निर्वाचन आयोग इस अपेक्षा पर खरा नहीं उत्तर पाता। पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है कि जब भी कई राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो मतदान की तारीखों में लंबा अंतर रखा जाता है। कई बार मतदान की तारीखों में लंबा अंतर रखा जाता है। कई चुनाव विशेषज्ञ इससे कई तरह की उलझनों पैदा होती हैं। कई चुनाव अधिकतम दो दिनों में बाटे जा सकते थे, जिससे खर्च कम बढ़ता और राजस्थान अपले तो लंबे समय तक नाहक अफरातफरी के माहौल में नहीं फैसे रहना पड़ता। जहां मतदान सबसे अंत में होगा, वहां सबसे लंबे समय तक चुनाव प्रचार चलेगा और

स्वाभाविक ही वहां के प्रशासनिक कामकाज में बाधा आएगी। इस तरह चुनाव की तारीखों को लंबे समय तक फैलाने के पीछे अक्सर निर्वाचन आयोग का तक होता है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उसे ऐसा फैसला करना पड़ा। मगर जब लोकसभा चुनाव भी लंगभग इनसे समय में संपन्न करा लिए जाते हैं, तो पांच राज्यों के चुनाव में भला सुरक्षाकालों की तैनाती में ऐसी क्या अड़चन आ सकती है। चुनाव के लंबे समय तक फैले होने से विपक्षी दलों को निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मोका मिल जाता है। पिंप, जहां पहले चरण में चुनाव होगा वहां की मतपरिणीयों की सुरक्षा के लिए लंबे समय तक पहरा बिटा कर रखना पड़ेगा। एक राज्य के मतदानों के रूपाना को दर्शा कर दूसरे राज्य के मतदानों को प्रभावित करने की कोशिशें तो होती ही। बहराहल अब चुनाव घोषित हो चुके हैं तो आवश्यक व संरूप प्रशासनिक मरीनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव में राजनीतिक दल नियम प्रक्रियाओं का पालन करें।

कविता

हो रहे
तैयार !



- कृष्णनंद राय

जीतने को बाज़ी ।
हो रहे तैयार ॥
लगा दें जो अब अब ।
बनना असरदार ॥
देनी उनको मात है ।
खोज रहे तरसीक ॥
ना हो जाए स्पॉत ।
आगे कुछ अजीब ॥
कर सही विश्लेषण ।
है निकलना हल ॥
आज से भी अच्छा ।
कर लेना है कल ॥
साध रहे निशाना ।
ना अब जाना चुक ॥
होता रहे कुछ भी ।
बैठना सकत मूक ॥

विनोद पाठक

सा डे नौ साल से केंद्र की सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट से कम नहीं होगा। यह चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सभी राज्यों में सकाराने ने लोक लुभावन घोषणाएं करने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन चुनावों में फोलीज या चुनावी रेवड़ियों की भी परीक्षा होने वाली है। विपक्ष के जातीय जनगणना के दाव पर जनता का रुख भी इन चुनावों में पता चलने वाला है।

राज्यवार बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस की सकरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले पांच साल से अपनी कुर्सी को बचाते आ रहे हैं। पांच साल में कई ऐसे अवसर आये, जब ताकि किंग होलोत की सकरातर गिर जाएगी। वर्ष 2020 में ठीक कोरोना के बीच कांग्रेस में बागवत हो गई थी। राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की सूझबूझ से सकारा बच तो गई, लेकिन मुख्यमंत्री निर्दलीय विधायकों पर आश्रित होकर रह गए। उसी का नीतीजा था कि मुख्यमंत्री गवर्नेंस से ज्यादा विधायकों को खुश करने में जुटे रहे। चुनाव से ठीक छह महीने पहले गहलोत ने लोकलुभावन घोषणाओं की ज़िंदी लगा दी। बिजली बिल माफी से लेकर मुफ्त मोबाइल बांटने तक शायद ही कई सेक्टर कराए गए, जिसके लिए गहलोत ने घोषणा न की हो। 33 से बढ़कर 53 जिले तक कर दिए गए। जाति के आधार पर बोर्ड बना दिए गए। गहलोत जहां अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपरलीक, तुष्टिकरण जैसे मुद्दों को आधा बना रहे हैं। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई में आपसी प्रतिद्वंद्वी के चलान नवरात्रि के चलाने पर लड़ा जा रहा है। रोशनी के लिए गहलोत ने लोकलुभावन घोषणाओं की बाजी लगा दी। बिजली बिल माफी से लेकर मुफ्त मोबाइल बांटने तक शायद ही कई सेक्टर कराए गए। पिछले बार कांग्रेस की सत्ता तक लाने वाले सचिन पायलट मौन हैं तो भाजपा की स्टर्न और पूर्व मुख्यमंत्री वसुधारा राजे को पार्टी में दर्किनार कर दिया गया है। राजस्थान में पिछले तीन दशक से हर पांच साल पर सत्ता बदलती आ रही है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि रिवाज बदलते था नहीं।

मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से चंद्र सीटें कम रह गई थीं। कांग्रेस ने युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया की जागह अनुभवी कमलनाथ को सत्ता की बागड़ेर सीट पर भी रखा है। लेकिन सिंधिया की बगवत के चलते भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई। शिवराज सिंह चौहान नियंत्रण में चुनाव राजनीति में अपनी विश्वास चौहान की कांग्रेस का चलाने रहे। अपनी भले चुनाव शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ा जा रहा है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की बागड़ेर सत्ता में लौटती है तो उन्हीं को कुर्सी मिलेगी, इसका कोई स्पष्ट संकेत पार्टी की ओर से नहीं आ रहा है। इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नियंत्रण से लेकर कदाचर कैलाश विजयवर्णीय, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को टिकट दिया है तो उससे भी शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी बढ़ी है। हालांकि, राज्य में भूपेश बघेल और टी.एस.सिंह देव में कुछ बैसी ही नोकझोक चलती रही, जैसी राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चलती रही। भूपेश बघेल की आधारीय जनता पार्टी ने नियंत्रण में चल रही थी। सत्ता में पुनः वापसी के लिए भूपेश बघेल ने भी चुनावी रेवड़ीयों का सहारा लिया है। अब तक बघेल काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पिछले पांच साल जानता पार्टी को प्रथमनांत्रे नियंत्रण में चलाने की भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। यहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रथमनांत्रे नियंत्रण में चलाने की भारतीय जनता पार्टी की भागड़ेर राजनीति है। उन्हें जनता पार्टी की बागड़ेर राजनीति है। उन्हें जनता पार्टी की बागड़ेर राजनीति है। उन्हें जनता पार्टी की बागड़ेर राजनीति है।

दक्षिण के राज्य तेलंगाना में केंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति सत्ता में है। राव वो बार से सत्ता में बने हुए हैं। जिस तरह से वर्ष 2018 में उन्हें बहुमत मिला था तो कहा जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊंचा है। हालांकि, राव भी सरकार विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। उन्हें जनता पार्टी के लिए भूपेश बघेल ने भी चुनावी रेवड़ीयों का सहारा लिया है। अब तक बघेल काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। उन्हें जनता पार्टी को प्रदर्शन किया जाता है कि वो यहां तो सीरी राजनीति को प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह देखते होंगे कि लोकसभा से पांच महीने पहले हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में यह गठबंधन एकजुट रहता है या नहीं। यदि आपसी प्रतिद्वंद्वी को छोड़कर इडिया गठबंधन के दल पांच राज्यों में एकजुट हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2024 में बड़ी चुनौती दे सकते हैं।

साभार : यह लेखक के अपने विचार हैं।

राजनीतिक आडंब

